

शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता पर सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक समीक्षा अध्ययनPandey, Bhupendra Kumar¹ and Karadwal, Sarita²¹Research Scholar , Department of Education, NIILM University, Kaithal (Haryana)²Research Supervisor, NIILM University, Kaithal (Haryana)**CITATION**

Pandey.B. K, & Karadwal.S, (2025). शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता पर सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक समीक्षा अध्ययन. *Shodh Manjusha: An International Multidisciplinary Journal*, 02(01), 183–193. <https://doi.org/10.70388/sm240129>

Article Info

Received: Dec 21, 2024

Accepted: Jan 23, 2025

Published: Mar 10, 2025

Copyright

This article is licensed under a license [Commons Attribution-Non-commercial-No Derivatives 4.0 International Public License \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

<https://doi.org/10.70388/sm240129>**सारांश**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारतीय शैक्षिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसे 34 वर्षों के बाद सभी स्तरों पर शिक्षा के दृष्टिकोण को पुनः संरचित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसे एक व्यापक और दूरदर्शी दस्तावेज के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, अनुकूलनीय और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है, साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषताओं में बहु-विषयक शिक्षा पर जोर, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को 2035 तक 50% तक बढ़ाना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण और प्रौद्योगिकी का शिक्षण में एकीकरण शामिल है। हालाँकि, एनईपी 2020 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे वित्तीय बाधाएँ, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, नियामकीय अवरोध और अवसंरचनात्मक खामियाँ। नीति बहु-विषयक शिक्षा ढांचे की स्थापना, बेहतर शिक्षण पद्धतियों और परीक्षा प्रणाली को प्राथमिकता देती है। लेकिन पाठ्यक्रम को उभरते रोजगार बाजारों के साथ संरेखित करने और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के मुद्दे अब भी प्रमुख चिंता के विषय हैं। एनईपी 2020 अनुसंधान और नवाचार के महत्व को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) जैसे पहलुओं के माध्यम से रेखांकित करता है और सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता को संबोधित करता है। यह शोध एनईपी 2020 के क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियों और अवसरों की पड़ताल करता है। द्वितीयक डेटा के आधार पर, यह सीमित संसाधनों, संस्थागत स्वायत्तता की कमी और ग्रामीण-शहरी शैक्षिक असमानताओं जैसे प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करता है।

अध्ययन प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता पर बल देता है। शोध यह निष्कर्ष निकालता है कि एनईपी 2020 भारत में शिक्षा के परिवर्तन के लिए एक दूरदर्शी मार्ग प्रदान करती है, लेकिन इसकी सफलता क्रियान्वयन चुनौतियों का समाधान करने और सतत सुधार, समावेशिता और अनुकूलनशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर निर्भर करती है। इन उपायों से नीति शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने और एक जीवंत और समतामूलक ज्ञान समाज के निर्माण में योगदान देगी।

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), नामांकन अनुपात, समावेशी, बहु-विषयक शिक्षा

परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने भारतीय शैक्षिक वातावरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। तीस साल के अंतराल के बाद अनावरण की गई इस ऐतिहासिक रणनीति का उद्देश्य देश में शिक्षा को देखने, व्यवस्थित करने और प्रदान करने के तरीके को मौलिक रूप से बदलना है। भारतीय शैक्षिक प्रणाली को बदलने के लक्ष्य के साथ, एनईपी 2020 एक दूरदर्शी घोषणापत्र है जो छात्रों को आलोचनात्मक, समग्र और वैश्विक रूप से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करता है (अख्तर, 2021)। यह नीति, जो माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा दोनों को कवर करती है, संरचनात्मक परिवर्तन लाती है, अनुकूलनशीलता को प्राथमिकता देती है, और एक शैक्षिक ढांचा विकसित करने के लक्ष्य के साथ विविधता को प्रोत्साहित करती है, जो न केवल इक्कीसवीं सदी की बदलती मांगों के प्रति संवेदनशील है, बल्कि भारतीय संस्कृति और नैतिकता में भी गहराई से समाहित है (कुमार, 2021)। हालांकि, इतनी व्यापक नीति का प्रभावी क्रियान्वयन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। यह अध्याय NEP 2020 के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली कठिनाइयों की गहन जाँच शुरू करता है, नीति संचार से लेकर वास्तविक कार्यान्वयन तक की समस्याओं को तोड़ता है। इसके साथ ही, हम उन संभावनाओं पर भी गौर करते हैं जो इन कठिनाइयों से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं, भारत के शैक्षिक वातावरण में क्रांतिकारी बदलाव की योजना तैयार करते हैं। NEP 2020 का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, समावेशी और नवीन बनाना है, जिससे छात्र न केवल शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक कौशल भी विकसित कर सकें। इस नीति के माध्यम से, सरकार उच्च शिक्षा में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है ताकि यह वैश्विक मानकों के अनुरूप हो सके। हालाँकि, इस नीति के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी हैं, जिनका विश्लेषण इस शोध में किया जाएगा। भारत में शिक्षा के भविष्य के लिए लक्ष्य और मार्ग को व्यापक और परिवर्तनकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में रेखांकित किया गया है। पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे

1986 में विकसित किया गया था और 1992 में संशोधित किया गया था, को एनईपी 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 29 जुलाई, 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) को अनुसंधान परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने और वित्तपोषित करने के साधन के रूप में सुझाया गया है, और बहु-विषयक शिक्षा का समर्थन किया गया है। पारंपरिक तरीकों से एक बड़ा विचलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना चाहती है जो अधिक अनुकूलनीय, समावेशी और इक्कीसवीं सदी की बदलती मांगों के अनुरूप हो। इस पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए भारत के शैक्षिक परिदृश्य में वांछित परिवर्तन लाने हेतु विभिन्न हितधारकों के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता होगी (मार्ने, 2022)।

शोध के उद्देश्य

- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 द्वारा सुझाए गए सुधारों का विश्लेषण करना।
- समावेशिता को बढ़ाने के लिए एनईपी 2020 के तहत प्रस्तावित नीतियों और प्रावधानों का मूल्यांकन करना।
- सुधारों के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनके प्रभावों की पहचान करना।
- शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए विभिन्न हितधारकों (सरकार, संस्थान, शिक्षक और समाज) की भूमिका और उनके योगदान का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

- शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता पर एनईपी 2020 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पूर्ववर्ती शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, और संबंधित लेखों की समीक्षा की जाएगी।
- शिक्षा के विभिन्न पहलुओं (जैसे नामांकन अनुपात, शिक्षकों का प्रशिक्षण स्तर, और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता) से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।
- उन क्षेत्रों या संस्थानों के अध्ययन का चयन किया जाएगा, जहाँ एनईपी 2020 को सफलतापूर्वक लागू किया गया है या जहाँ इसे लागू करने में प्रमुख चुनौतियाँ सामने आई हैं।
- प्राप्त आंकड़ों और मामलों का विश्लेषण सांख्यिकीय और गुणात्मक तरीकों से किया जाएगा ताकि सुधारों के प्रभाव और सीमाओं को समझा जा सके।

- नीति निर्माताओं, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से साक्षात्कार के माध्यम से उनकी राय और अनुभवों को एकत्रित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश को एक समतामूलक, टिकाऊ और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देने के लिए इसकी परंपरा, संस्कृति, मूल्यों और लोकाचार पर विचार करके भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है। अपनी विशाल और लंबी ऐतिहासिक विरासत से इनपुट प्राप्त करके और गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुकला, जहाज निर्माण और नेविगेशन, योग, ललित कला, शतरंज आदि जैसे विविध क्षेत्रों में दुनिया के कई विद्वानों के योगदान को ध्यान में रखते हुए, संपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना और निर्माण किया गया है। वर्तमान में घोषित एनईपी 2020 का उद्देश्य वर्तमान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 2035 तक 50% तक बढ़ाने के लिए प्रत्येक आकांक्षी को एक बहु-विषयक और अंतःविषय उदार शिक्षा प्रदान करना है। भारत, शैक्षिक सुधारों के लिए एक बढ़ता हुआ उदार देश है, वर्तमान में लगभग 845 विश्वविद्यालयों और लगभग 40,000 शिक्षा संस्थानों (एचआईई) को दर्शाता है, देश में कुल मिलाकर उच्च विखंडन और कई छोटे आकार के उच्च शिक्षा संस्थान हैं इन विश्वविद्यालयों से संबद्ध। शिक्षा काफी हद तक एक निजी वस्तु है। शिक्षा के खरीदार सीधे तौर पर उस चीज से लाभान्वित होते हैं जिसके लिए वे भुगतान करते हैं। हालाँकि, शिक्षा को अक्सर एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में भी देखा जाता है, मुख्य रूप से इसके सकारात्मक प्रभावों के कारण। भारत मुफ्त है, लेकिन इसके स्कूल नहीं हैं - सुधारों का ध्यान इस पर होना चाहिए - निजी स्कूलों के लिए स्वायत्तता और सरकारी स्कूलों के लिए गुणवत्ता! सरकारी स्कूल उतने ही अच्छे हैं या ठीक-ठीक कहें तो सरकारी अस्पतालों जितने ही बुरे हैं। उनका प्रबंधन ठीक से नहीं किया जाता है और कई स्कूल भूतहा स्कूल बन गए हैं। NEP का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी भारतीयों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। NEP 2020 की सबसे बड़ी सफलता यह है कि यह कम विनियमन, अधिक स्वायत्तता, बेहतर शिक्षण और सीखने के तरीकों, बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण और अधिक सार्थक परीक्षाओं की आवश्यकता को पहचानती है; अनिवार्य रूप से, इसने भारत को भविष्य के लिए एक दृष्टि दी है। हालाँकि, इसने एक यथार्थवादी तरीका नहीं दिया है जिससे निजी संस्थान अपने छात्रों और अपने समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटा सकें। शैक्षणिक संस्थान न तो परोपकार के ज़रिए पर्याप्त धन जुटा पाए हैं और न ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपनी ट्यूशन फीस बढ़ा पाए हैं। सबसे अच्छे समय में भी, परोपकारी योगदान अविश्वसनीय होते हैं और किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए फंडिंग का मुख्य स्रोत नहीं हो सकते हैं। फीस को स्वस्थ

सामर्थ्य से परे नहीं बढ़ाया जा सकता है। NEP एक ऐसी रणनीति पर दोगुना ज़ोर देती है जो विफल हो चुकी है और यह कहती रहती है कि निजी शिक्षण संस्थानों को केवल परोपकार के ज़रिए ही अपना धन जुटाना चाहिए। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 और कोविड-19 महामारी ने NEP द्वारा प्रचारित वित्तीय मॉडल की कमज़ोरियों को उजागर किया है। परोपकारी योगदान नगण्य होने और फीस वसूली में कमी के कारण, कई संस्थान अब संकट में हैं और अपने शिक्षकों को वेतन देने, अपने ऋण चुकाने या दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हैं। यह फिर से शैक्षणिक संस्थानों को एक तरल कोष बनाने की अनुमति देने की आवश्यकता को दर्शाता है जिसे निवेश और बचत की जा सकती है, और जिसका उपयोग कठिन समय के दौरान किया जा सकता है। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपना लिया है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और स्कूल से बाहर के 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ, नीति की भावना परिवर्तनकारी है। यह भारतीय लोकाचार के मूल सिद्धांतों और शिक्षा में तकनीकी उपकरणों को अपनाने के वैश्विक रुझानों के बीच संतुलन बनाता है। नीति को अक्षरशः लागू करना, विशेष रूप से राज्यों के माध्यम से, चुनौतीपूर्ण होगा। शिक्षा एक समवर्ती विषय है, इसलिए कार्यान्वयन में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2005 से, हर साल, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट - ASER, लगातार दिखाती रही है कि बच्चों का पढ़ने और अंकगणित का स्तर चिंताजनक रूप से कम है। पंद्रह साल पहले, ग्रामीण भारत में कक्षा V के लगभग आधे बच्चे कक्षा II के स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने में असमर्थ थे। जहाँ तक मुझे पता है, यह संख्या लगभग अपरिवर्तित बनी हुई है। इस साल कोरोना महामारी ने इसे और भी बदतर बना दिया है। स्कूली शिक्षा का प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष बच्चों के क्रमिक समूहों के लिए कम और कम "मूल्य" जोड़ रहा है। शुरुआती वर्षों में मजबूत नींव बनाने की आवश्यकता है ताकि बच्चे "आगे छलांग लगा सकें"। आज हम जो "पीछे छूटने" की व्यापक घटना देखते हैं, वह इसलिए होती है क्योंकि सही चीजें सही समय पर नहीं की जाती हैं। जिन बच्चों को अपने शुरुआती वर्षों में अच्छी शुरुआत का लाभ नहीं मिला, उनके लिए "एक ही जैसा और अधिक" या "हमेशा की तरह काम करना" काम नहीं करेगा। "पकड़ने" के आकार, गहराई और परिमाण को देखते हुए, हमें कम से कम पाँच साल या उससे अधिक समय तक लगातार और उच्च प्राथमिकता वाले प्रयास की आवश्यकता होगी। भारत भर के सरकारी स्कूलों में चार में से एक शिक्षक अनुपस्थित है और दो में से एक, जो मौजूद है, पढ़ा नहीं रहा है। 10% शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करते हैं - इसका मतलब है कि 90% पात्रता परीक्षा में असफल होते हैं। शिक्षक छात्रों की शैक्षणिक सफलता के सबसे महत्वपूर्ण स्कूल-आधारित निर्धारक हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शिक्षक की अनुपस्थिति छात्रों की उपलब्धि को कम करती है।

साहित्य समीक्षा

प्रियंका (2024) ने कहा कि भारत में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के रूप में जाना जाने वाला एक ऐतिहासिक प्रयास, इक्कीसवीं सदी की बदलती मांगों के अनुकूल इसे अनुकूलित करने के लिए शैक्षिक प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का लक्ष्य रखता है। यह अध्याय इस बात पर गौर करता है कि एनईपी 2020 को कैसे लागू किया जा रहा है, भारत की शैक्षिक प्रणाली में बदलाव के साथ आने वाली संभावनाओं और समस्याओं पर प्रकाश डालता है। अध्ययन के लिए प्राथमिक डेटा स्रोत द्वितीयक डेटा है। परिणाम एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं, जो भारत में शिक्षा सुधार के बारे में निरंतर बातचीत में इजाफा करता है। पहचाने गए मुद्दों से निपटने के लिए सुझाव दिए गए हैं, जिसमें एक सहकारी और लचीली रणनीति के विकास पर जोर दिया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों और आबादी की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। यह अध्याय शिक्षा संक्रमण के बदलते और गतिशील भूभाग को नेविगेट करने में भारत की सहायता करना चाहता है।

मंडल (2023) ने प्रस्तावित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो भारत में शिक्षा के भविष्य के लिए दृष्टि और दिशा को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र एनईपी 2020 का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, इसके निहितार्थों की जांच करता है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, उनकी पहचान करता है। यह शोध पत्र पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन और शासन में बदलावों सहित एनईपी 2020 के प्रमुख प्रावधानों का पता लगाता है और शिक्षा प्रणाली पर उनके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा, यह समग्र और बहु-विषयक शिक्षा, डिजिटलीकरण और समावेश पर नीति के जोर से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करता है। इस शोध के निष्कर्ष शैक्षिक सुधारों पर चल रहे विमर्श में योगदान करते हैं, जो नीति निर्माताओं, शिक्षकों और NEP 2020 के कार्यान्वयन में शामिल हितधारकों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

उच्च शिक्षा सुधार में एक और महत्वपूर्ण चुनौती अकादमिक कार्यक्रमों और उभरते नौकरी बाजार के बीच संरेखण है। कई स्नातक खुद को ऐसे कार्यबल में प्रवेश करते हुए पाते हैं जो पारंपरिक रूप से उनके डिग्री कार्यक्रमों में जोर नहीं दिए जाने वाले कौशल की मांग करता है। इस वियोग ने पाठ्यक्रम प्रासंगिकता और सॉफ्ट स्किल्स, आलोचनात्मक सोच और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देने के महत्व के बारे में बातचीत को बढ़ावा दिया है। शैक्षणिक संस्थानों को उद्योग के नेताओं के साथ सहयोग करने के लिए तेजी से कहा जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अकादमिक कार्यक्रम छात्रों को तेजी से बदलती

अर्थव्यवस्था में कामयाब होने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करें। हालाँकि, इस सरिखण को प्राप्त करने के लिए निरंतर संवाद और दोनों पक्षों की ओर से अनुकूलन की इच्छा की आवश्यकता होती है (अल्टबैक, 2014).

इसके अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण उच्च शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरे हैं। शैक्षणिक जीवन के दबाव, वित्तीय तनाव और सामाजिक अपेक्षाओं जैसे बाहरी कारकों के साथ मिलकर छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में वृद्धि हुई है। संस्थान व्यापक सहायता सेवाएँ प्रदान करने के महत्व को पहचानने लगे हैं जो न केवल शैक्षणिक सफलता बल्कि भावनात्मक कल्याण को भी संबोधित करती हैं। इसमें एक ऐसा परिसर संस्कृति बनाना शामिल है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, सहकर्मि सहायता नेटवर्क को बढ़ावा देता है, और परामर्श और संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करता है। हालाँकि, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को सार्थक तरीके से संबोधित करने के लिए संस्थानों से महत्वपूर्ण निवेश और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

उच्च शिक्षा का परिदृश्य एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है, जिसमें सुधार और चुनौती दोनों शामिल हैं। सुलभता, सामर्थ्य, गुणवत्ता आश्वासन, तकनीकी एकीकरण और कार्यबल के साथ सरिखण के लिए जोर एक अधिक उत्तरदायी शैक्षिक प्रणाली की आवश्यकता की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। हालाँकि, इन सुधारों को अपनाना अपनी कठिनाइयों के बिना नहीं है (एस्टेनॉल, 2015) संस्थानों को विविध छात्र आवश्यकताओं, उद्योग की बदलती मांगों और गुणवत्ता और अखंडता को बनाए रखने की अंतर्निहित चुनौतियों के जटिल अंतर्संबंध का सामना करना चाहिए। चूंकि हितधारक इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होते रहेंगे, इसलिए उच्च शिक्षा का भविष्य शिक्षा के मूल मिशन के प्रति सच्चे रहते हुए परिवर्तन को अपनाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा: व्यक्तियों को सशक्त बनाना और समाज को समृद्ध बनाना।

भारत की सबसे बड़ी चुनौती गरीबी है, हमें लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है और हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक हम प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से शुरू होती है जब बच्चा 5 साल का होता है। प्राथमिक शिक्षा का मतलब केवल एक कक्षा, किताबें और एक शिक्षक (जो न्यूनतम है) नहीं है, बल्कि पोषण, कपड़े और ऐसा माहौल बनाना है जहाँ बच्चा हर दिन नई चीजें सीख सके, ऐसा माहौल जो बच्चे के भीतर सर्वश्रेष्ठ को सामने लाने में मदद कर सके। कुर्सी, मेज, किताबें, स्टेशनरी, एक कक्षा और शिक्षक जैसी बुनियादी संरचना न्यूनतम है जो कोई भी सरकार प्रदान कर सकती है। उन्हें इससे कहीं अधिक करने की आवश्यकता है जैसे बच्चों को यह सिखाना कि वे कैसे कल्पना कर सकते हैं और अपनी आंतरिक प्रतिभा को बाहर ला सकते हैं जिसका उपयोग वे बाद में अपने जीवन में कर सकते हैं।

हालाँकि दूसरी तरफ़ उच्च शिक्षा इस समस्या का समाधान नहीं करती है। उच्च शिक्षा तब शुरू होती है जब आप हाई स्कूल या 10+2 पास कर लेते हैं। इसलिए अगर बच्चा 5 साल का है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में रहता है तो बच्चे को उच्च शिक्षा की नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा की ज़रूरत है। इसलिए अगर सरकार सिर्फ़ उच्च शिक्षा पर खर्च कर रही है तो इससे बच्चे की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि उच्च शिक्षा का मतलब सिर्फ़ कॉलेज है। और जब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में रहने वाला बच्चा 16 साल की उम्र तक पहुँचता है तो उसका दिमाग पहले ही बन चुका होता है। इसलिए अगर सरकार उच्च शिक्षा पर खर्च कर रही है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उच्च और प्राथमिक शिक्षा में यही अंतर है।

उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के बीच का अंतर शैक्षिक परिदृश्य का एक मूलभूत पहलू दर्शाता है, जो अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करता है और व्यक्ति के जीवन में विभिन्न विकासात्मक चरणों की पूर्ति करता है। प्राथमिक शिक्षा, जो आम तौर पर औपचारिक स्कूली शिक्षा के पहले कुछ वर्षों को शामिल करती है, साक्षरता, अंकगणित और दुनिया के बारे में बुनियादी ज्ञान में आधारभूत कौशल प्रदान करने पर केंद्रित होती है। इसका उद्देश्य बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी उपकरणों से लैस करना और आजीवन सीखने की नींव रखना है। इसके विपरीत, उच्च शिक्षा में अक्सर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उन्नत अध्ययन शामिल होता है, और इसे विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान को गहरा करने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और छात्रों को पेशेवर करियर के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उद्देश्यों में यह असमानता शिक्षा के प्रत्येक स्तर में निहित भिन्न पद्धतियों, पाठ्यक्रमों और छात्र अनुभवों को रेखांकित करती है (भूषण, 2016)।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार, उद्योग, शैक्षिक संस्थान, माता-पिता और छात्रों से कुछ सुझाव और अपेक्षाएँ हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्राथमिक से उच्च शिक्षा स्तर तक अभिनव और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षण संस्थानों को गुणवत्ता और प्रतिष्ठा में सुधार करने की आवश्यकता है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का एक अच्छा बुनियादी ढांचा होना चाहिए जो छात्रों को आकर्षित कर सके। सरकार को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों और शीर्ष अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए और बेहतर गुणवत्ता और सहयोगी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शीर्ष संस्थानों के अनुसंधान केंद्रों के बीच संबंध भी बनाना चाहिए। स्नातक छात्रों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता है जिसमें वे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें, विषय का गहन ज्ञान प्राप्त कर सकें ताकि उन्हें कंपनियों में भर्ती होने के बाद नौकरी मिल सके जिससे उच्च शिक्षा के लिए

अनावश्यक भीड़ कम हो सके। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को राजनीतिक संबद्धता से दूर होना चाहिए, पक्षपात, पैसा कमाने की प्रक्रिया को शिक्षा प्रणाली से बाहर रखा जाना चाहिए (बौग्नोल, 2015) उच्च शिक्षा में बहुविषयक दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों का ज्ञान केवल उनके अपने विषय तक ही सीमित न रहे।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता के बाद सभी विषयों में उच्च शिक्षा संस्थानों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी भारत विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने में बहुत पीछे है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 9% से अधिक है। विकास की उस दर को बनाए रखने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले संस्थानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। भविष्य की आवश्यकताओं को प्राप्त करने और उन तक पहुँचने के लिए वित्तीय संसाधनों, शिक्षा नीतियों, पहुँच और समानता, गुणवत्ता मानकों, प्रासंगिकता और अंत में जवाबदेही पर फिर से विचार करने की तत्काल आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए कुछ घटक विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। शिक्षण पद्धति या शिक्षण सहित शैक्षणिक विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के माध्यम से कर्मचारियों का सावधानीपूर्वक चयन और निरंतर कर्मचारी विकास होना चाहिए। हमें देशों के बीच, उच्च शिक्षा संस्थानों और कार्य की दुनिया के बीच गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, साथ ही देशों के भीतर और बीच में छात्रों की गतिशीलता पर भी ध्यान देना चाहिए। ताकि वे काम करने के माहौल के बारे में जान सकें। आंतरिक स्व-मूल्यांकन और बाह्य समीक्षा स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा, यदि संभव हो तो, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ, खुले तौर पर और समय-समय पर की जानी चाहिए। यदि भारत की बात करें तो हम दुनिया को कुशल और शिक्षित लोग दे रहे हैं। हम अपने देश को विकासशील से विकसित देश बनाने के लिए उनकी क्षमता का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित लोगों को शामिल करने के लिए कुछ मापदंड बनाने होंगे। हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जो ज्ञान के मापदंडों से परिभाषित होगा। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो आधुनिक/उन्नत, उदार हो और बदलते समाज, बदलती अर्थव्यवस्था और बदलती वैश्विक दुनिया की बदलती मांगों के अनुकूल हो सके। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली और नियामक निकायों को प्रमुख मुद्दों की पहचान करनी चाहिए और उन बाधाओं को दूर करने के लिए जल्दी से नीतियां बनानी चाहिए। केवल एक या दो विश्वविद्यालय बहुत अंतर नहीं ला सकते। यदि सरकार ऐसी पहलों का स्वागत करती है जो हमारी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाती हैं, तो भविष्य हमारा होगा। हम अन्य देशों के साथ मुकाबला करने में सक्षम होंगे और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना पूरा करना मुश्किल नहीं होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत में उच्च शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है जो लंबे समय से पहुंच, गुणवत्ता और प्रासंगिकता के मुद्दों से जूझ रही है। एनईपी 2020 में कई महत्वाकांक्षी सुधारों को स्पष्ट किया गया है, जिनका उद्देश्य अधिक न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बनाना है। प्राथमिक लक्ष्यों में से एक 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 50% तक बढ़ाना है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों सहित हाशिए के समूहों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वंचित क्षेत्रों में अधिक संस्थान स्थापित करके और इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करके, नीति दशकों से चली आ रही शैक्षिक खाई को पाटने का प्रयास करती है।

संदर्भ

1. अग्रवाल, एस.पी., भारत में शिक्षा का विकास-चयनित दस्तावेज 1995 - 97 - वी, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, 1999.
2. अग्रवाल, जे.सी., आधुनिक शिक्षा का विकास और योजना, विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड; 576 मस्जिद रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली, 1997।
3. अग्रवाल, बी.बी., 1854 से 1899 तक ब्रिटिश भारत में शैक्षिक नीति का विकास, पीएच.डी.ई.यू. दिल्ली विश्वविद्यालय, 1980।
4. अब्देलकाफी एन., हिलबिग आर., और लॉडियन एसएम (2018)। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उद्यमी विश्वविद्यालयों के व्यवसाय मॉडल - एक खोजपूर्ण विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, 77(1/2/3), 86-108।
5. अल्टबैक पी. (2014). भारत की उच्च शिक्षा चुनौतियाँ। एशिया पैसिफिक एजुकेशन रिव्यू, 15, 503-510.
6. कपूर डी., और मेहता पी.बी. (2004)। भारतीय उच्च शिक्षा सुधार: आधे-अधूरे समाजवाद से आधे-अधूरे पूंजीवाद तक (सीआईडी वर्किंग पेपर नंबर 108)। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी।
7. कापलान ए.एम., और हेनलेन एम. (2016)। उच्च शिक्षा और डिजिटल क्रांति: MOOCs, SPOCs, सोशल मीडिया और कुकी मॉन्स्टर के बारे में। बिजनेस होराइजन, 59, 441-450।

8. कुमार, ए., सामाजिक शोध की पद्धति, अल्फा प्रकाशन, 4398/5, प्रथम तल, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, 2008.
9. कुमारन एस., और राजकुमार टी. (2019)। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे में भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रकाशन: एक अध्ययन। लाइब्रेरी फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, 2553, 1-11।
10. कुरियन, अजय और चंद्रमना, सुदीप. (2020). नई शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षा पर प्रभाव. 10.6084/m9.figshare.13332413.v1.
11. कोचर, एस.के., भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण मुद्दा, नई दिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, 1981.
12. डॉ. अजय पाल सिंह ढिल्लों (2021), एनईपी 2020: उच्च शिक्षा का परिवर्तन; इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन एंड रिव्यूज, खंड 2, संख्या 12, पृष्ठ 1101-1105, दिसंबर 2021
13. डॉ. प्रेम सोनवाल (2021), राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और उच्च शिक्षा; इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न मैनेजमेंट, एप्लाइड साइंस एंड सोशल साइंस (आईजेईएमएमएसएसएस) 55 आईएसएसएन: 2581-9925, इम्पैक्ट फैक्टर: 6.340, खंड 03, संख्या 03(आई), जुलाई-सितंबर, 2021, पृष्ठ 55-59
14. ढोलकिया पी.एम. (2006, 24 जनवरी)। मुक्त शिक्षा कार्यक्रम को टिकाऊ बनाने वाला क्या है? यह संस्करण, 1-5. <https://www.oecd.org/education/ceeri/36781781.pdf>
15. तिवारी, अंशुमान. (2022). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षक शिक्षा को सशक्त बनाना. पेरिपेक्स इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च. 78-80. 10.36106/पेरिपेक्स/7008072.
16. दास, प्रसेनजीत और दास, गौरी। (2024)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: उच्च शिक्षा को बदलने के लिए अनुसंधान और नवाचार। 62. 20-27. 10.5281/zenodo.10845051.
17. देवी, रेणु, असम में शिक्षा की प्रगति, ओमसंस प्रकाशन, जसोबंता रोड, गुवाहाटी, 1987
18. देसाई, डी.एम., भारत में सार्वभौमिक अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय बॉम्बे, 1953.
19. नंदा ए. (2016, 4 मार्च)। उच्च शिक्षा केवल वित्तपोषण के बारे में नहीं है। बिजनेस लाइन, पृष्ठ 8।
20. नाइक, जे.पी., शिक्षा आयोग और उसके बाद, ए.पी.एच प्रकाशन निगम, नई दिल्ली, 1997. शर्मा, आर.ए., शैक्षिक अनुसंधान के मूल सिद्धांत, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, पोस्ट बॉक्स नंबर 64, मेरठ, 250001, 1995.